

कावेरी प्राधिकरण ने कर्नाटक को पानी छोड़ने के नरिदेश दिये

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अपनी पहली बैठक में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) ने कर्नाटक को तमलिनाडु और अन्य राज्यों के लिये पानी छोड़ने के नरिदेश दिये हैं लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में CWMA के गठन को चुनौती देने के कर्नाटक के फैसले पर बैठक में चर्चा नहीं की गई।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- कर्नाटक सरकार ने हाल ही में CWMA और कावेरी जल वनियमन समिति (CWRC) की स्थापना के वरिद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला लिया था। अपील में उसने मांग की थी कि इस कदम को लेकर संसद में चर्चा की जानी चाहिये।
- CWMA ने कर्नाटक को बलिंगुंडुलु साइट से 34 tmcft (हजार मिलियन घन फीट) पानी छोड़ने का नरिदेश दिया था। यह जून में छोड़े गए पानी से अधिक होगा।
- CWMA, जो अभी तक पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति नहीं कर सका है, मानसून महीनों के दौरान प्रत्येक 10 दिनों में बैठक करेगा।
- वभिन्न जलाशयों- हेमावथी, हरंगी, कृष्णराजासागर, कबीनी, मेटतूर, भवानीसागर, अमरावती और बनसुरासागर में पानी के भंडारण के आधार पर यह सफ़ारिश करेगा कि 10 दिनों में इन बलों में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को ध्यान में रखते हुए कतिना पानी छोड़ा जाना चाहिये।
- उच्चतम न्यायालय द्वारा फरवरी में दिये गए फैसले में कहा गया था कि कर्नाटक को 284.75 tmcft, तमलिनाडु को 404.25 tmcft तथा केरल और पुदुचेरी को क्रमशः 30 और 7 tmcft पानी मिलेगा।

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) का गठन

- CWMA में टकिू बस्विल, एस.के. प्रभाकर, ए.अंबरसु और राकेश सहि (केरल के सचिव) शामिल हैं। इसके अलावा तमलिनाडु, पुदुचेरी और कर्नाटक के जल आयोग तथा केंद्रीय कृषि और जल संसाधन मंत्रालय के प्रतिनिधि इसकी देखभाल करते हैं।
- CWMA की अध्यक्षता एक वरिष्ठ और प्रतिष्ठित इंजीनियर या सचिव/अतिरिक्त सचिव स्तर के कार्यकारी अधिकारी द्वारा की जाएगी, जसै अंतर-राज्य जल विवादों के प्रबंधन का अनुभव हो।
- प्राधिकरण के लिये दो पूर्णकालिक और छह अंशकालिक सदस्य होंगे, जनिमें से प्रत्येक को नदी तट पर स्थिति राज्यों से नामति किया जाएगा।
- सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्वसिज़ कैंडर से एक सचिव होगा, लेकिन उसे वोटिंग का अधिकार नहीं होगा।
- अध्यक्ष का कार्यकाल पाँच साल होगा, जबकि अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा और इसे पाँच साल तक बढ़ाया जा सकता है।